वर्ष-12//अंक-35//अगस्त// 2024
ISSN 2454–5805

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

हरेली पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बिखरी छटा

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी होगी सुनिश्चितः मोदी

समस्याओं के समाधान केंद्र सीएम साय का जनदर्शन

14

महतारी वन्दनः रुपया हजार, खुशियां अपार

22

अब वनाश्रितों को जंगल में चलने-फिरने में नहीं होगी तकलीफ

34

नए कीर्तिमान खड़ा कर दी मनु भाकर

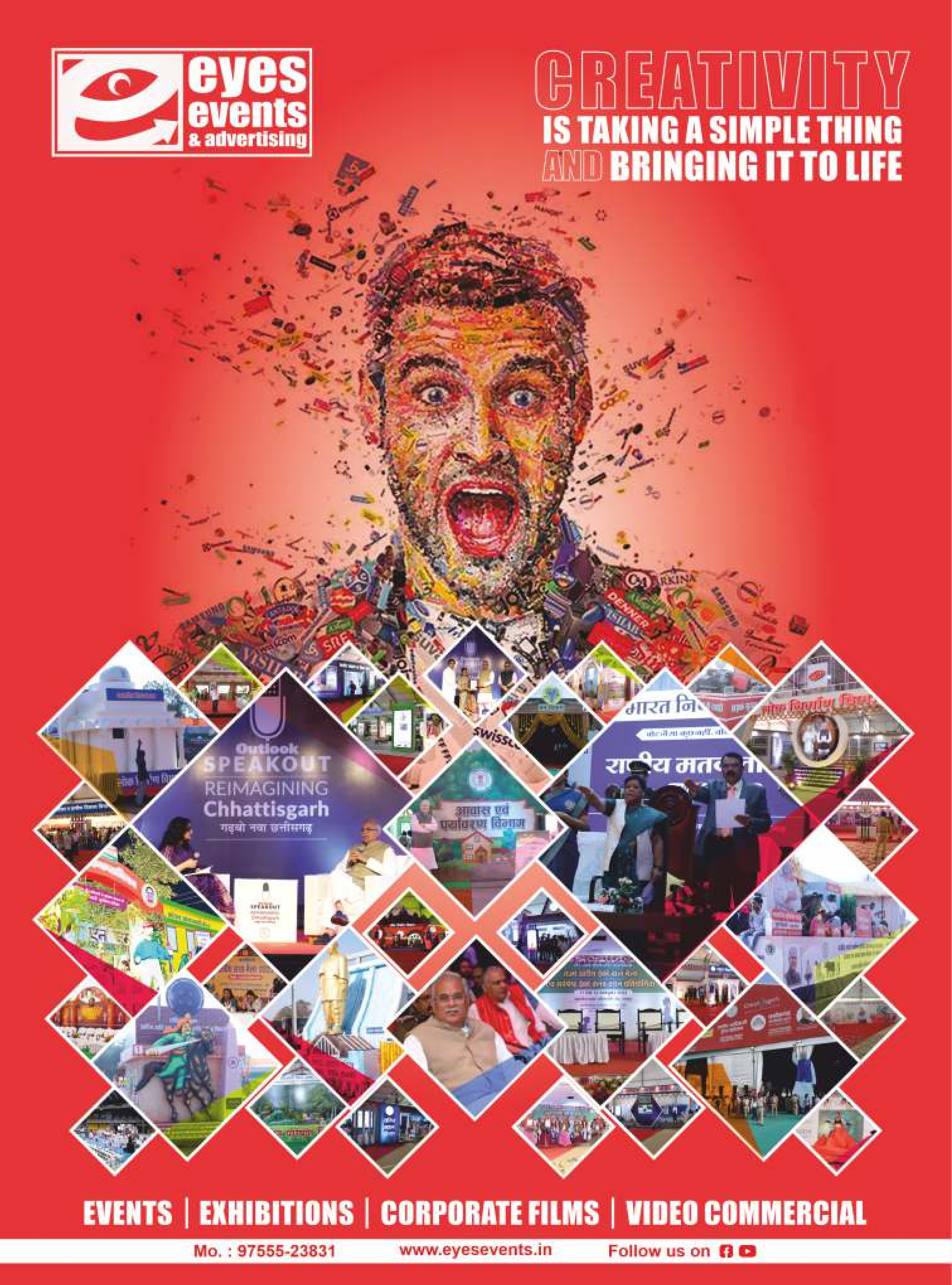
eyes events & advertising
CREATIVITY
IS TAKING A SIMPLE THING
AND BRINGING IT TO LIFE
Outlook
SPEAKOUT
REIMAGINING
Chhattisgarh
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़
आवास एवं
पर्यावरण विभाग
EVENTS | EXHIBITIONS | CORPORATE FILMS | VIDEO COMMERCIAL
Mo. : 97555-23831
www.eyesevents.in
Follow us on

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-12//अंक-35//अगस्त//2024

प्रबंध संपादक	:	उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	:	प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	:	नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	:	प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	:	देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	:	जितेन्द्र साहू
मार्केटिंग मैनेजर	:	किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	:	कुसुम श्रीवास्तव
अकाउंट असिस्टेंट	:	प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	:	योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

54/111, सालासर बालाजी मंदिर के पास,
अग्रसेन धाम के पीछे, वी.आई.पी.रोड, रायपुर (छ.ग.)

फोन : 0771-4044047

ईमेल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अगस्त 2024

इस अंक में

छत्तीसगढ़ में अन्य कामों के शुभारंभ के लिए भले ही श्री गणेश जी की आराधना की जाती है लेकिन अब महीने की पहली तारीख माँ की वंदना अर्थात महतारी वंदन के साथ हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महीने की पहली तारीख को क्लिक कर प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जो अंतरित करते हैं। यह राशि पहली तारीख को इसलिए दी जाती है क्योंकि यह दिन नये महीने की बजट की शुरुआत का होता है। यह अतिरिक्त राशि गृहिणी के खाते में जुड़ती है और स्वाभाविक रूप से इसे खर्च करने का पूरा विवेक उसका होता है।

20

रोजगार गारंटी योजना.... श्रमिकों की ताकत बनकर उभर रही

08

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास आदि।

जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता

12

भारत सरकार मृदा परीक्षण आधारित सिफारिश के आधार पर जैविक और जैव उर्वरक के साथ उर्वरक के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री

16

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ. वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है.

नियद नेल्लानार योजना से बदल रही गाँवों की तस्वीर

28

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 'नियद नेल्लानार योजना' शुरू की गई है।

आखिरकार क्यों देश छोड़ गई शेख हसीना?

32

बांग्लादेश में जारी आरक्षण आंदोलन में जारी हिंसा फिलहाल थमती नहीं दिख रही। इसमें शेख हसीना की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और चुपचाप देश से निकल गईं।

ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हर लुक में बेहद हॉट सनी लियोनी

38

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक सनी लियोनी ने इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, उन्होंने बोल्ड और इंटिमेट सीन्स देकर अपना एक अलग ही लेवल सेट कर लिया है.

राहतों के सुशासन में त्वरित निराकरण की खुशियां

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

छत्तीसगढ़ सरकार ने छह माह में ही मोदी की गारंटी पर मुहर लगाकर गहरा विश्वास आम जनता के बीच बनाया है। सुशासन वाली सरकार से अपेक्षाओं का दौर काफी है। हालांकि समस्याओं का पूरा-पूरा निदान एक बड़ी जिम्मेदारी है। याद करें जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पहली बार जून के महीने में अपने निवास पर जनदर्शन की शुरूआत की, उस समय काफी भीड़ उमड़ी। यह भीड़ विश्वास की भीड़ थी, तभी तो दूर-दराज से लोग सीएम हाउस में पहुंच गए। वैसे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है। इस वजह से राहतों का सिलसिले को अंजाम तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। जो समस्याएं हाउस में आम नागरिकों ने गुहार लगाई, वह तत्काल एक झटके में पूरा हो गया। उम्मीदों के साथ आशाएं बढ़ी और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप सरकार आम नागरिकों के घरों तक समस्याओं का निराकरण करने के लिए पहुंच गई।

शुरू हुआ जन समस्या निवारण पखवाड़ा शिविर। इस शिविर से आमजन को काफी राहत मिल रही है। क्योंकि छोटी-मोटी समस्याएं तुरंत में निराकृत हो रही है। प्रशासन की पहुंच घर-घर तक पहुंचने से लोग राहत महसूस कर रहे है। इससे प्रशासन के कामकाज भी लंबित नहीं हो रहे है और लोगों को विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल रही है। एक और सबसे अच्छी बात है कि हर स्तर पर लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए जिला प्रशासन भी सजग है और सक्रियता के साथ कर्तव्य निभा रही है। यही वजह है कि कलेक्टरों के जनदर्शन से भी तत्काल समस्या का निराकरण हो रहा है।

इसके अलावा अब ऑनलाइन माध्यम भी शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। यानी रायपुर जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए कॉल सेंटर शुरू की। कॉल सेंटर से राहतों का दौर भी शुरू हो गया है। बेहतर मॉनीटरिंग के साथ इसका असर देखने को भी मिल रहा है और इसका परिणाम भी सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय की संवदेनशील पहल का नतीजा है कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन के साथ कार्य किया जाएं। सबसे बेहतर कार्य यह भी है कि अधिकारियों को गांव-गांव में योजनाओं की हकीकत को जानने और समस्याओं को दूर करने के लिए भेजने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इससे गांव के हर नागरिकों तक पहुंचकर अधिकारी समस्या लेकर आएंगे और समस्या का निदान भी जिला मुख्यालय से तुरंत किया जाएगा। यह सब संभव श्री साय के मंशा के अनुरूप ही हो पाया है।

Hyundai Exter Knight Edition लॉन्च, शुरुआती कीमत 8.38 लाख, जानें डिजाइन और फीचर्स

हुंडई ने एक्सटर का नाइट एडिशन लॉन्च किया है. इस स्पेशल वेरिएंट में कुछ खास स्टाइल अपडेट किए गई हैं. कंपनी ने एक्सटर के लॉन्च के एक साल पूरे होने पर नया एडिशन लॉन्च किया है. इसमें ऑल ब्लैक थीम और रेड हाईलाइट्स दी गई हैं.

Hyundai EXTER Knight का डिजाइन

हुंडई एक्सटर नाइट के बाहरी हिस्से को कई स्पोर्टी तत्वों के साथ डिजाइन किया गया है. इसमें ब्लैक-पेंटेड साइड सिल गार्निश और फ्रंट बम्पर और रियर टेलगेट दोनों पर लाल रंग के एक्सेंट शामिल हैं. वाहन में रेड फ्रंट ब्रेक कैलीपर्स और ब्लैक फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स भी दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त, यह काले रंग के R15 एलॉय व्हील्स (SX(O) Connect), काले रंग का हुंडई लोगो (सवहव), काले रंग का एक्सटर प्रतीक और एक विशेष नाइट प्रतीक (Knight emblem) के साथ आता है.

Hyundai EXTER Knight का केबिन

एसयूवी के केबिन को भी अलग बनाने की पूरी कोशिश की गई है. ऑल-ब्लैक थीम से सजे केबिन को रेड एक्सेंट से पूरा किया गया है. ये रेड एक्सेंट फ्लोर मैट, एयर कंडिशन वेंट्स और स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिलता है. इसके अलावा इक्यूपमेंट लिस्ट ज्यादातर स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है. इसमें सीटों पर नाइट एडिशन की बैजिंग दी गई है.

Hyundai EXTER Knight Edition का इंजन

एक्सटर नाइट एडिशन में 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 83hp की पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल रहा है.

Hyundai EXTER Knight में कलर ऑप्शन

ये कार 5 मोनोटॉन औ 2 डुअल टोन कलर में उपलब्ध होगी. इसमें आपको Starry Night, Atlas White, Ranger Khaki, Abyss Black (नया), Shadow Grey (नया), Ranger Khaki with abyss black roof और Shadow grey with abyss black roof (नया) कलर मिलता है.

नई हुंडई एक्सटर नाइट एडिशन की कीमत 8.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और एएमटी गियरबॉक्स वाले टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए 10.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी होगी सुनिश्चितः मोदी

◆ **बजट 2024-25 पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का मूल पाठ**

देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव-गरीब-किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नीयो मीडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानि की लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी।

रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने Employment Linked Incentive Scheme की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे।

इस योजना के तहत, जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह, हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गाँव, हर घर entrepreneurs बनाना हैं। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर, मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से MSME सेक्टर की ownership मध्यमवर्गीय है। और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है।

छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है। मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। E-Commerce Export Hubs और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी।

ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकॉनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड हो, Angel Tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकॉनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स देश में नए सैटलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए Transit Plans...इससे देश में नए economic hub विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। ज्वै के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास...पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं।

अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं। इससे एक ओर छोटे किसानों को फल-सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे...तो दूसरी ओर, हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल-सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए, दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, Saturation Approach के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना, 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को All Weather Roads से जोड़ेगी। इसका लाभ, देश के सभी राज्यों के दूर-दराज गांवों को मिलेगा। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये Better Growth और Bright Future लेकर आया है। आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के, उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा।

रोजगार गारंटी योजना....

श्रमिकों की ताकत बनकर उभर रही

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक भलाई में सुधार करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इस संबंध में, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (**WDC-** पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों को लागू कर रही है। ग्रामीण विकास की योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत बजटीय आवंटन में वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। योजनाबद्ध दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए तथा जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए धनराशि आवंटित की जाती है।

मनरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है, जिसके तहत हर परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। यह ग्रामीण परिवारों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने पर आजीविका के अन्य विकल्प प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, यह वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार अनिवार्य करता है और सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। राज्य सरकारों के पास अपने फंड का उपयोग करके गारंटीकृत अवधि से परे रोजगार के अतिरिक्त दिन आवंटित करने का विकल्प है।

इस मंत्रालय की सभी योजनाओं/ कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार और आजीविका के अवसरों के सृजन सहित ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। रोजगार के अवसर पैदा करने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदायों सहित ग्रामीण लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए, जहाँ भी लागू हो, यह मंत्रालय कई योजनाओं जैसे कि एमजीएनआरईजीएस, डीडीयू - जीकेवाई और आरएसईटीआई को लागू कर रहा है।

जबकि एमजीएनआरईजीएस ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देता है, डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मजदूरी या स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देती हैं। हालाँकि, यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से कोई रोजगार गारंटी योजना लागू नहीं करता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना को लागू कर रहा है, जिसके तहत दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रदान करके उन्हें वेतन/स्वरोजगार में शामिल किया जाएगा, जिससे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों, आर्थिक रूप से

पिछड़े वर्गों आदि सहित समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं सहित देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है।

इसी प्रकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है, जो एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

समस्याओं के समाधान केंद्र सीएम साय का जनदर्शन

- श्रमिक परिवारों को दी 11 करोड़ 41 लाख रूपए की सहायता राशि
- बड़ी संख्या में हुआ मौके पर ही आवेदनों का निराकरण

जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों का एक बार फिर आमजनों में उत्साह दिखा, रिमझिम बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। इस बार एक और बात को लेकर लोगों में उत्साह दिखा वह हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरूआत की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आने वाले लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6 हजार 200 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रूपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रतीक स्वरूप 12 हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी.दयानंद सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंची महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में यह योजना कारगर सिद्ध हो रही है। महिलाओं ने बताया कि बहनों की राखी इस बार शानदार रहेगी। भाईयों के लिए अच्छी मिठाईयां खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी

महासमुन्द निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलको से भी मुलाकात की और उनकी हौसल अफजाई की। इन खिलाड़ियों ने बताया कि 20 से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल हुड बॉल में हिस्सा लेने दक्षिण कोरिया जा रही है।

रायपुर जिले के ग्राम पंचायत परसुलीडीह के सरपंच के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परसुलीडीह के स्कूल भवन में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को जल्द से जल्द शेड निर्माण करने के निर्देश दिए। बलौदाबाजार जिले के डोंगरिया के किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केमिकल प्लांट से खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जल्द राहत दिलाने कहा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने रायपुर शहर के चौरसिया कॉलोनी की 18 वर्षीय सना परवीन, ग्राम सेरीखेड़ी की निवासी कोमल लहरे, और धमतरी जिले के ग्राम कचना के निवासी ठगिया साहू को मोटराईज्ड ट्राई सायकल प्रदान किया।

रक्षाबंधन के तोहफे में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

मुख्यमंत्री से बिलासपुर की रिशी अग्रवाल और बेमेतरा जिले की सिद्धका गोस्वामी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राखी के पूर्व मेरे लिए राखी लेकर आई है और आपने मेरे हाथों में राखी बांध दिया। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों का स्नेह मुझ पर है। रक्षाबंधन का तोहफा मैं आपको अनुकंपा नियुक्ति के रूप में जल्द प्रेषित करूंगा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जमीन का जल्द मिलेगा मुआवजा

बालोद निवासी बोधन लाल ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि उनकी जमीन अंडा में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें भू-अर्जन की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने इस पर बालोद कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई कर भू अर्जन की राशि दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भू अर्जन से प्रभावित अन्य लोगों को भी शीघ्र राहत देने के निर्देश दिए।

लक्ष्य के इलाज की होगी व्यवस्था

रायपुर के फाफाडीह के रमण मंदिर वार्ड से आए रोशन साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका बेटा 8 साल का लक्ष्य एस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर बीमारी से पीड़ित है। इसके इलाज के लिए उन्हें अहमदाबाद इसके लिए नियमित रूप से जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी समस्या सुनकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चे की बीमारी के संबंध में इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लक्ष्य के पिता ने कहा कि मैं बच्चे का लंबे समय तक इलाज करते हुए परेशान हो गया था और हिम्मत हार चुका था अब मुख्यमंत्री के मिलने के बाद मुझे नई उम्मीद जगी है।

खपरी गांव को मिलेगी जर्जर सड़कों से मुक्ति

जनदर्शन कार्यक्रम में बालोद जिला के ग्राम पंचायत खपरी ब की सरपंच जनक बाई साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि ग्राम ईरागुड़ा से पायला पहुंच मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, जिससे राहगीरों को आने-जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने गांव की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनकर शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की बात कही। साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया।

जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता

◦ उर्वरक के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित

भारत सरकार मृदा परीक्षण आधारित सिफारिश के आधार पर जैविक और जैव उर्वरक के साथ उर्वरक के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता तथा सतत उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक और जैव उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए ''धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)'' नामक योजना को लागू कर रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को जैविक और प्राकृतिक खेती तथा जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए उर्वरक सब्सिडी की बचत का 50 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सरकार ने किण्वित जैविक खाद, तरल किण्वित जैविक खाद और जैविक उर्वरकों के उपयोग के लिए 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता की भी घोषणा की है। सरकार वर्ष 2015-16 से देश में मृदा स्वास्थ्य और जल धारण क्षमता में सुधार के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है। दोनों ही योजनाओं में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तथा कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक सभी प्रकार की सहायता देने पर बल दिया गया है और साथ ही टिकाऊ कृषि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की कुल सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, भागीदारी गारंटी प्रणाली-भारत प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटक सम्मिलित हैं। इसमें से किसानों को तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक निवेश के लिए प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है।

जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक निवेश, गुणवत्ता वाले बीजध्रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रमाणन के लिए किसानों को सहायता देने के लिए 3 वर्षों के लिए कुल 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के अंतर्गत किसानों को 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक निवेश के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को सीधे बैंक अंतरण के रूप में 15,000 रुपये और राज्य अग्रणी एजेंसी (राज्य अग्रणी एजेंसी) द्वारा किसानों को रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये दिए जाते हैं।

ये सुविधाएं करा रहे उपलब्ध

राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र और गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इम्फाल और भुवनेश्वर में स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र विभिन्न मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम,

जैसे एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण, विस्तार अधिकारियोंध्कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण, भागीदारी गारंटी प्रणाली-भारत पर दो दिवसीय प्रशिक्षण, 30 दिन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 500 प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय जैविक एवं प्राकृतिक किसान सम्मेलन, 100 प्रतिभागियों के लिए प्राकृतिक कृषि पर एक दिवसीय हितधारक परामर्शध्सम्मेलन, प्राकृतिक खेती पर उन्नयन कार्यक्रम और जैविक और प्राकृतिक कृषि के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जैविक और जैव-उर्वरकों के खेत उत्पादन और उपयोग के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) और क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र (आरसीओएनएफ) जैविक और प्राकृतिक खेती और जैविक और जैव-उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग पर ऑनलाइन जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है और अग्रिम प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करती है।

महतारी वन्दनः रुपया हजार, खुशियां अपार

रायपुर. यह महतारी वंदन योजना है. एक ऐसी योजना, जिसमें सुनहरे भविष्य की उम्मीद और बेबस, लाचार महिलाओं के साथ-साथ अपने जरूरी खर्चों के लिए पैसों की मोहताज महिलाओं की खुशियां ही नहीं छिपी है, इन खुशियों के पीछे आर्थिक सशक्तिकरण का वह आधार भी है, जो कि महतारी वंदन जैसी योजना के बलबूते छत्तीसगढ़ की गरीब महिलाओं में आत्मनिर्भरता की नींव को शनैः-शनैः मजबूत करती जा रही है.

महज चार महीनों में ही विष्णु सरकार की इस महतारी वंदन योजना ने छत्तीसगढ़ की न सिर्फ महिलाओं में अपितु घर-परिवार में भी खुशियों की वह मिठास घोल दी है, जिसका परिवर्तन उनके जीवनशैली में भी बखूबी नजर आने लगा है. आर्थिक रूप से सशक्तिकरण ने परिवार के बीच रिश्तों की गाँठ को और भी मजबूती से बाँधना शुरू कर दिया है. इस योजना से महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है.

छत्तीसगढ़ में इस साल के 10 मार्च से महिलाओं के खाते में भेजी गई पहली किश्त एक हजार रुपए से आरंभ हुई छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लगभग 70 लाख 12 हजार से अधिक महिलाओं को मिल रहा है. साल में 12 हजार रुपये कोई छोटी रकम नहीं है. यह जरूरतमंद गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार भी है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विगत चार महीनों से लगातार हर महीने के पहले सप्ताह में महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना अंतर्गत एक हजार की राशि ऑनलाइन माध्यम से अंतरित करते हैं. मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही महिलाओं के खाते में पहुँचने वाली यह राशि प्रदेश की लाखों महिलाओं की खुशियों का पर्याय बन जाती है. पहले कुछ रुपयों के लिए मोहताज महिलाओं को एक हजार की राशि मिलने पर उनकी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों का सपना भी पूरा होता है. इस राशि का उपयोग वह सिर्फ अपने ही लिए नहीं करती...घर के राशन से लेकर अचानक से पति को कुछ रुपयों की पड़ी आवश्यकता, बच्चों के लिए कुछ जरूरी सामान, नाती-नतनी की खुशियों के खातिर स्नेहपूर्वक उन्हें उनकी जरूरतों का उपहार देने में भी करती हैं. महिलाओं को हर महीने इस राशि का बेसब्री से इंतजार रहता है.

ऐसी ही इस योजना की हितग्राही मीरा बाई हैं. पति शारिरिक रूप से असमर्थ है. किसी तरह मजदूरी कर घर के खर्चों को पूरा करती है. तीन बच्चे हैं और वे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं. स्कूल खुलते ही अपने बच्चों के लिए आई जरूरतों को पूरा करने के साथ घर की जरूरतों में भी महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग करती हैं. उन्होंने बताया कि घर के प्रति उनकी जिम्मेदारी है और हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है.

इस राशि से ऐन वक्त पर बच्चों और पति को आई जरूरतों को भी पूरा कर पाती हैं. गाँव में रहने वाली सविता बाई के पति खेतों में काम करते हैं. बारिश में चाय की चुस्कियां लेती सविता बाई ने महतारी वंदन न्याय योजना का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान लाकर इस योजना से मिल रही खुशियों को प्रकट किया. उन्होंने कहा कि गाँव की महिलाओं के लिए एक हजार की राशि एक बड़ी राशि होती है. उन्होंने बताया कि महिलाओं की आदत होती है कि दो-चार-पाँच रुपए बचा कर सौ-दो सौ जोड़ लें. यहां तो एक हजार रुपए मिल रहे हैं ऐसे में उनकी जरूरतों के लिए यह रकम कठिन समय में संजीवनी की तरह साबित हो रही है. बच्चों के लिए भी वह इस राशि को खर्च कर पाती है. उन्होंने बताया कि पैसा खाते में आने के बाद छोटी जरूरतों के लिए पति से अनावश्यक पैसा मांगना भी नहीं पड़ता.

वनांचल में रहने वाली श्रीमती बुधवारों बाई राठिया गाँव के हाट बाजार पहुँची थीं. अपने नाती आशीष को लेकर आईं बुधवारो बाई ने बाजार में नाती को न सिर्फ उनके पसंद का मिष्ठान खिलाया अपितु अन्य नाती-नतनिनों के लिए बाजार से मिष्ठान

लिया और उनका नाती आशीष बारिश में नंगे पैर न घूमे इसे ध्यान रखते हुए महतारी वंदन योजना की राशि से स्नेहपूर्वक चप्पलें भी खरीदी. उन्होंने बताया कि उनका जो कुछ है उनके बेटे और नाती-नतनी ही हैं और बहुत ही खुशी मिलती है कि वृद्धावस्था में वह अपने नाती-नतनियों की कुछ जरूरतों को पूरा कर पाती हैं. यह सब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार की बदौलत ही हो पाया है. उन्होंने हमारे संघर्षमय जीवन में खुशियों की मिठास घोल दी है.

केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ. वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है. यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है. छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है. इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है. रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है. इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी. इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है. जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है. यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है. भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे. इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा. उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं. 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी. नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है. टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी. उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है. इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है.

मध्यप्रदेश में अब मेट्रो का सफर हुआ लंबा

◦ एयरपोर्ट रोड से रत्नागिरि तक बनेगी 6 लेन सड़क ◦ करोंद में बनेगा थ्री टियर ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम

भोपाल। अब करोंद तक पहुँचेगी मेट्रो। करोंद चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर। एयरपोर्ट रोड से रत्नागिरी तक बनेगी 6 लेन सड़क। करोंद में बनेगा थ्री टियर ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम, जिसमें ऊपर चलेगी मेट्रो बीच में फ्लाईओवर और नीचे से गुजरेगा सर्विस रोड। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत करोंद चौराहे पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन का स्थल निरीक्षण किया। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट प्रथम फेज के अंतर्गत लगभग 30 किमी रूट के ऑरेंज लाइन कॉरिडर के तहत करोंद चौराहे पर मेट्रो स्टेशन बनने व रूट बनने का कार्य शुरू हो गया है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि करोंद में मेट्रो स्टेशन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वहीं एनएचएआई द्वारा शीघ्र ही फ्लाईओवर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इससे करोंद चौराहे पर थ्री टियर ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम तैयार होगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने मेट्रो परियोजना, समस्त संबधित विभागों, नेशनल हाईवे, लो.नि.वि, नगर निगम, ट्रेफिक पुलिस, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा जिला प्रशासन की समन्वय समिति की बैठक कर निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिये।

4 वर्षों में पूर्ण होगा निर्माण कार्य

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट प्रथम फेज के अंतर्गत लगभग 30 किमी रूट प्रस्तावित है, जिसमें ऑरेंज लाइन कॉरिडर करोंद से एम्स तक लगभग 16 किमी की होगी। इसमें 2 भूमिगत स्टेशन (भोपाल जंक्शन एवं नादरा बस स्टैन्ड) एवं 14 एलेवेटेड स्टेशन होंगेस अब करोंद से मेट्रो की लाइन लगने का कार्य शुरु हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही एनएचएआई द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट से रत्नागिरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। वहीं करोंद चौराहे पर एनएचएआई द्वारा फ्लाईओवर प्रस्तावित है।

यह निर्माण कार्य 4 वर्षों में पूरे होंगे। मेट्रो एवं एनएचएआई की दोनों ही परियोजनाओं में विलंभ न ही हो तथा कंस्ट्रक्शन के दौरान यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो इसके लिये मेट्रो परियोजना, एनएचएआई, पीडब्लूडी, नगर निगम, यातायात एवं जिला प्रशासन की कॉर्डिनेशन टीम गठित कर सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

समन्वय समिति की बैठक कर बाधाओं का करें निराकरण

मंत्री श्री सारंग ने मेट्रो ट्रेन तथा करोंद चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के एलाइनमेन का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ किया जाये। मेट्रो परियोजना के अधिकारी सभी संबधित विभागों, नेशनल हाईवे, लो.नि.वि, नगर निगम, ट्रेफिक पुलिस, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा जिला प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करें एवं यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझसे संपर्क करें तथा समय समय समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर कार्य की गति की तीव्र करने एवं बाधाओं के निराकरण व समाधान करें।

करोंद चौराहे पर फ्लाईओवर से 5 लाख की जनसंख्या को होगा लाभ

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि इस परियोजना से लगभग 4 लाख जनसंख्या को लाभ मिलेगा। करोंद चौराहे पर ट्रैफिक जाम की कठिनाई के निराकरण के लिये लगभग 2 किमी लम्बाई में फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रारंभ किया जा रहा है।

मेट्रो लाईन इस फ्लाईओवर के उपर से निकलेगी, जिसमें सम्पूर्ण चौराहे में फ्लाईओवर तथा मेट्रो के कोई पिलर नहीं होंगे व इस चौराहे का विकास भी उत्कृष्ट रूप से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से चौराहे के विकास के साथ तीन सब-वे का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को चौराहे क्रास करने में असुविधा नही हो तथा मेट्रो स्टेशन तक आसानी से पहुंच सके।

करोंद को उपनगर बनाने की दिशा में निरंतर हो रहा कार्य

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि भोपाल मेट्रो नरेला विधानसभा के लिये बहुत बड़ी सौगात है। यह भोपाल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आयेगी। उन्होंने कहा कि करोंद को भोपाल का उपनगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। करोंद चौराहे को विश्व स्तरीय चौराहे के रूप में विकसित करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। मेट्रो एवं फ्लाईओवर का कार्य पूरा होने के बाद करोंद भोपाल का सबसे व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा।

सुभाष नगर से करोंद स्टेशन के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर पर हो रहा मिट्टी परीक्षण कार्य

ऑरेंज लाइन करोंद से एम्स तक लगभग 16 किमी की होगी। इसमे 2 भूमिगत स्टेशन (भोपाल जंक्शन एवं नादरा बस स्टैन्ड) एवं 14 एलेवेटेड स्टेशन होंगेस ऑरेंज लाइन पर सुभाष नगर से करोंद स्टेशन के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर पर मिट्टी परीक्षण का कार्य किया जा रहा है एवं जल्द ही अन्य कार्य प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें 17 मीटर के पीयर का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा।

महिलाओं के खाते में पईसा सांय-सांय

◦ महिलाएं अपने बचत के स्वभाव के अनुरूप राशि बचाएंगी

छत्तीसगढ़ में अन्य कामों के शुभारंभ के लिए भले ही श्री गणेश जी की आराधना की जाती है लेकिन अब महीने की पहली तारीख माँ की वंदना अर्थात महतारी वंदन के साथ हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महीने की पहली तारीख को क्लिक कर प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जो अंतरित करते हैं। यह राशि पहली तारीख को इसलिए दी जाती है क्योंकि यह दिन नये महीने की बजट की शुरुआत का होता है। यह अतिरिक्त राशि गृहिणी के खाते में जुड़ती है और स्वाभाविक रूप से इसे खर्च करने का पूरा विवेक उसका होता है।

पहली अगस्त को गई यह छठवीं किश्त है। जुलाई सत्र में बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और अगस्त के महीने में भी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित खर्चे होते हैं। माताओं-बहनों ने अपने बजट के हिस्से में इसके लिए भी राशि लगाई होगी। देश बचत से भी आगे बढ़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो लंबे समय से सकल घरेलू बचत का अनुपात अच्छा होने का सकारात्मक असर आर्थिक सेहत पर पड़ा। महिलाओं ने छोटे-छोटे खर्च बचाकर, छोटी-छोटी खुशियों की आहूति देकर जो बचत की, उससे परिवारों का बचत बढ़ा और यह देश की बचत राशि में जुटा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जो राशि दे रहे हैं उससे निश्चित ही महिलाएं अपने बचत के स्वभाव के अनुरूप राशि बचाएंगी। यह चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ती जाएगी और आड़े वक्त में जब परिवार के लिए राशि की जरूरत होगी तो वे खर्च कर पाएंगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। बैंक खाते में यह राशि जा रही है और स्वाभाविक रूप से बैंकिंग सिस्टम में राशि होने से बचत के काम आयेगी। इसके साथ ही डीबीटी होने की वजह से पारदर्शिता से महिलाओं के खाते में पहुंच रही है। यह विष्णु का सुशासन है जिसमें डिजिटल टेक्नालाजी सर्वोपरि है। पारदर्शिता है। जरूरी नहीं कि यह निवेश वे सीधे बैंकिंग तंत्र, जीवन बीमा अथवा म्यूच्युअल फंड आदि माध्यमों से ही कर रही हों, वे अपना निवेश बच्चों की शिक्षा में लगा रही है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी शिक्षा में निवेश किया गया, उसके सबसे अच्छे परिणाम सामने आये हैं। हमारे यहां माता जीजा बाई का उदाहरण हैं जिन्होंने अपने यशस्वी पुत्र शिवाजी को एक महान उद्देश्य के लिए तैयार किया, शिक्षित किया। शिवा जी जैसे योग्य पुत्रों के पोषण के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी माताओं-बहनों को हम आर्थिक शक्ति प्रदान करें।

धरती का श्रृंगार पेड़ों से करना होगा

महतारी वंदन का एक रूप धरती माता की सेवा भी है। जलवायु परिवर्तन का संकट दुनिया के सबसे बड़े संकटों में से एक है। हम सब सामान्य नागरिक इस संकट का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में इसे आंदोलन के रूप में आरंभ किया है। उन्होंने अपने स्कूल में रूद्राक्ष का पौधा अपनी माँ के नाम लगाया। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि वे एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। मुख्यमंत्री ने जो स्कूल में पौधा लगाया, उसके कई मायने हैं। स्कूल में जब हम पौधा लगाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण से जोड़ते हैं। जिस पीढ़ी को इन पेड़ों को सहेजना है उसे इस संबंध में जागरूक करते हैं। केवल जलवायु परिवर्तन के संकट को रोकने के लिए नहीं, हमने इस धरती से जो लिया, अपने पुरखों से

जो लिया, उसे धरती को लौटाने भी हमें है। धरती माता का ऋण हमारे ऊपर है। हमें धरती का श्रृंगार पेड़ों से करना होगा तभी हम इस ऋण से ऋण हो सकेंगे।

आगे की पीढ़ी का उज्ज्वल भविष्य छिपा

जब हमारी माताएं महतारी वंदन योजना के अंतर्गत निवेश करती हैं तो वे बचत का एक पौधा बोती हैं जो कालांतर में विशाल वृक्ष के रूप में तैयार होगा। जब हमारी माताएं बहनें इस अभियान के साथ एक पौधा लगाएंगी तो यह पौधा भी विशाल वृक्ष के रूप में तैयार होगा। अपनी मेहनत जब विशाल और फलदायी रूप में सामने आयेगी तो कितना संतोष इन महिलाओं को होगा। महतारी वंदन योजना और एक पेड़ मां के नाम दो अलग-अलग बातें नहीं हैं वे एक ही हैं और इसमें हमारी आगे की पीढ़ी का उज्ज्वल भविष्य छिपा है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लागू होने के साथ ही महिलाओं में नया आत्मविश्वास दिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना की लोकप्रियता शहरों के साथ-साथ गांवों में भी दिख रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना से राज्य के 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ छह माह से मिल रहा है।

महतारी वंदन योजना एप्प जारी

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी योजना में 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के मोबाइल में मेसेज आते ही परिवार के बच्चे खुशी से कह उठते हैं कि हमर मोबाइल में सांय-सांय पईसा

आवत हे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन को सटीक और बेहतर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना एप्प जारी किया गया है। महतारी वंदना योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी का मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।

हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू

महतारी वंदन योजना में हर माह राशि आने का असर अब दिखने लगा है। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएँ अपना फैसले खुद ले रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगाने में यह योजना सफल हुई है। इस योजना से महिलाओं को उनके रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मदद मिल रही है। इस राशि से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। महिलाओं को मिले इस आर्थिक स्रोत से परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के अध्यापन कार्य तथा उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने में कर रही हैं।

महतारी वंदना योजना से महिलाओं को आगे बढने के लिए रास्ता मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी नवाचारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिला समूहों को आर्थिक क्रियाकलपों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहान योजना भी संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान लगभग 3100 स्व-सहायता समूहों को 100 करोड़ रूपए की राशि का ऋण वितरित किया है। इससे महिलाओं में स्वावलंबन और आर्थिक रूप से निर्भरता आएगी।

अब वनाश्रितों को जंगल में चलने-फिरने में नहीं होगी तकलीफ

- छात्राएं अब स्कूल से घर फट से करेंगी आना-जाना
- चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना का ऐलान

छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी।

गरीबों के लिए समर्पित सरकार : मुख्यमंत्री

दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए

इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है।

मोदी सरकार का मिल रहा पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णोद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।

हर वर्ग के हित में अहम निर्णय

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पौधे लगाएं जाएंगे। श्री कश्यप ने इस अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो पौधा उपस्थित महिलाओं को दिया है, उसका रोपण और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। बस्तर के जंगलों में प्रभु श्रीराम के चरण पड़े हैं, यही कारण है कि बस्तर के जंगलों में एक भी कांटे नहीं हैं, हमारे जंगल हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जबसे छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार बनी है, तबसे हर वर्ग के हित में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार घोषणापत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस दिशा में काम हो रहा है। जगदलपुर विधायक किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार चुनाव के पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें प्रदेश वासियों की सहभागिता जरूरी है। किरण देव ने कहा कि घर-परिवार, समाज को चलाने वाली माताओं-बहनों की परेशानियों की चिंता कर उनकी जरूरतें पूरी करने महतारी वंदन योजना शुरू करना वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान है और सरकार इस योजना से मातृशक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास कर रही है।

3061 समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। नगर पालिक निगम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजाना के अन्तर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया गया जिसमें प्रथम किस्त में 10 हजार, द्वितीय किस्त 20 हजार, तृतीय किस्त में 50 हजार की राशि देय होगी जिसके तहत तीन लोगों को 80 हजार का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय द्वारा दिवंगत 13 शासकीय कर्मचारियों के वारिसन को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। पांच मृत वनाधिकार पट्टेधारकों के वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका प्रदान की गई।

हरेली पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बिखरी छटा

- किसानों को ट्रेक्टर, हार्वेस्टर का वितरण
- सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति का अनूठा नजारा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, यहां की 80 प्रतिशत आबादी का जीवन-यापन कृषि पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर खेती-किसानी को समृद्ध बनाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित हरेली तिहार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण जैसी सुविधाएं सुलभ करायी गई। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रूपए का मूल्य मिल रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व पर रंगारंग आयोजन हुआ। पूरे परिसर को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के पहले पर्व "हरेली" पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी धर्मपत्नि कौशल्या देवी साय के साथ

गौरी-गणेश पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले नांगर, रापा, कुदाल व कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा वहां लगायी गयी उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अनुदान पर 23 किसानों को ट्रेक्टर और हार्वेस्टर की चाबी और अन्य कृषि उपकरण प्रदान किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पूरी प्रतिबद्धता और सच्चे मन से प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, फलस्वरूप ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल रहा है। प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते छह माह में श्री साय के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए बड़े काम किए गए है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।

मुख्यमंत्री निवास में राउत नाचा और गेड़ी धूम

छत्तीसगढ़ी संगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक गड़वा बाजा, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य, रहचुली और विभिन्न छत्तीसगढ़ी पकवानों और व्यंजनों के आनंद के साथ मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोग उत्साह के साथ हरेली में शामिल हुए। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने राउत नाचा, करमा नृत्य, बस्तरिया नृत्य और गेड़ी चढ़कर नृत्य की प्रस्तुति दी। राउत नाचा के कलाकारों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

मेहमानों के लिए बना छत्तीसगढ़ी पकवान

हरेली त्यौहार के मौके पर मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ व्यंजनों से महक उठा। हरेली तिहार में आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर ठेठरी, खुरमी, पिड़िया, अनरसा, खाजा, करी लड्डू, मुठिया, गुलगुला भजिया, चीला-फरा, बरा जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे, जिसका मेहमानों ने लुत्फ उठाया।

एक चित्रः छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहरों का संकलन

छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां हर एक अवसर और कार्यों के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों एवं वस्तुओं का उपयोग किया जाता रहा है। इस चित्र में पारंपरिक वस्तुओं को एक ही जगह पर दिखाया गया। जो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर का हिस्सा है। इनमें –

काठा : इस चित्र में सबसे बाएं दो गोलनुमा लकड़ी की संरचना दिख रही है, जिसे काठा कहा जाता है। पुराने समय में जब गांवों में धान मापन के लिए तौल कांटा बाट का प्रचलन नही था, तब काठा से धान का मापन किया जाता था। सामान्यत: एक काठा में चार किलो धान आता है। काठा में ही नाप कर पहले मजदूरी के रूप में धान का भुगतान किया जाता था।

खुमरी : सिर के लिए छाया प्रदान करने के लिए बांस की पतली पतली टुकड़ों से बनी, गुलाबी रंग से रंगी और कौड़ियों से सजी घेरेदार संरचना खुमरी कहलाती है। यह प्राय: गौ वंश चराने वाले चरवाहा मवेशी चराते समय अपने सिर पर धारण करते है। जिससे धूप और बारिश से राहत मिलती है। पहले चरवाहा कमरा और खुमरी लेकर पशु

चराने निकलते थे। कमरा जो कि जूट के रेशे से बने ब्लैंकेट नुमा मोटा वस्त्र होता था। जो कि बारिश के समय ओढ़ने से आसानी से पानी अंदर नहीं जाता था। कमरा को रेनकोट की तरह ओढ़ने के काम में लिया जाता था।

कांसी की डोरी : खुमरी के बगल में डोरी का गोलनुमा गुच्छा कांसी पौधे के तने से बनी डोरी है। यह पहले चारपाई या खटिया में उपयोग होने वाले निवार के रूप में प्रयोग किया जाता था। डोरी बनाने की प्रक्रिया को डोरी आंटना कहा जाता है। बरसात के शुरुआती मौसम के बाद जब खेत के मेड़ों में कांसी पौधे उग आते है। तब उसके तने को काटकर डोरी बनाई जाती थी। जो कि चारपाई बनाने के काम आती थी।

झांपी : चित्र के सबसे दाएं तरफ ढक्कन युक्त लकड़ी की गोलनुमा बड़ी संरचना झाँपी कहलाती है। यह पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ में बैग या पेटी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता था। यह खासकर विवाह के अवसर पर बारात जाने के समय दूल्हे का कपड़ा, श्रृंगार समान, पकवान आदि सामग्रियां रखने का काम आता था। यह बांस की लकड़ी से बनी मजबूत संरचना होती थी, जो कई वर्षों तक आसानी से खराब या नष्ट नहीं होती थी।

कलारी : बांस के डंडे के छोर पर लोहे का नुकीली हुक लगा हुआ वस्तु कलारी कहलाता है। यह प्राय: धान मिंजाई के दौरान उपयोग में लाया जाता था। यह धान को मिंजते समय धान को उलटने पलटने के काम आता था.

मध्यप्रदेश में निवेश और व्यवसाय की भरपूर संभावनाएं......

देश की समृद्ध खनिज संपदा और औद्योगिक विकास का प्रतीक

मध्यप्रदेश को मिल चुका है मिनरल ऑक्शन के लिए पहला पुरस्कार

मध्यप्रदेश भारत के खनन और खनिज क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को लगातार साबित कर रहा है, जिससे उल्लेखनीय उपलब्धियाँ और भविष्य की संभावनाएँ सामने आ रही हैं, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगी। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिवसीय बेंगलुरू यात्रा हुई है। जहाँ उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश के लिये प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि मिनरल ऑक्शन के लिये मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिल चुका है।

मध्यप्रदेश में जल्दी ही एल्युमिनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन मैंगनीज के 33 ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। इसी प्रकार 17 कोल ब्लॉक के ऑक्शन भी प्रक्रिया में है। प्रमुख खनिजों के 20 ब्लॉक ऑक्शन की प्रक्रिया में है। इनमें मैंगनीज, डायमंड बॉक्साइट, लेटराइट, गोल्ड, बेस मेटल और लाइमस्टोन हैं। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश में खनिज संपदा में निवेश की बहुत ज्यादा संभावना बनी हैं। पिछले साल एक साथ 51 ब्लॉक का आक्शन हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मध्यप्रदेश में पाए

जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों में कोयला, लाइमस्टोन, डायमंड और पायरोफ्लाइट है। मध्यप्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहां सिंगरौली, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और नरसिंहपुर भरपूर कोयला भंडार है। कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट्स और कोल गैसीफिकेशन प्लांट्स में होता है। इनसे संबंधित उद्योगों के लिए निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। इसी प्रकार चूना पत्थर का भी प्रदेश में भरपूर भंडार है। यहां रीवा, सतना, सीधी, मैहर, दमोह, कटनी पन्ना, धार और नीमच में भरपूर भंडार है। देश के कुल लाइमस्टोन भंडार का 9% मध्यप्रदेश में है। इस दृष्टि से सीमेंट उद्योग के लिए मध्यप्रदेश एक आदर्श निवेश स्थान है। यहां जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार हुआ है इस दृष्टि से भी मध्यप्रदेश से देश के सभी राज्यों का संपर्क बेहतर हो गया है।

देश में उपलब्ध डायमंड भंडार का 90% मध्यप्रदेश में पाया जाता है। यह अकेले पन्ना और छतरपुर में है। इस दृष्टि से यहां डायमंड बिजनेस पार्क और और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 5 ब्लॉक की पहचान की गई है। मध्यप्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। यहां देश के उत्पादन का 41% उत्पादन हो रहा है। देश में सर्वाधिक भंडार 14 मिलियन टन मध्यप्रदेश में है, जो छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ में है। इसके भंडारण को देखते हुए देश में सेरेमिक, पॉटरी, पोर्सलिन और टाइल्स उद्योगों के लिए सबसे लाभकारी निवेश स्थान है।

समृद्ध खनिज संपदा

पूरा मध्यप्रदेश खनिज संपदा से भरा पड़ा है। ग्वालियर और शिवपुरी में आयरन और क्वार्ट्ज और फ्लैगस्टोन पाया जाता है। झाबुआ और अलीराजपुर में रॉक फास्फेट डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज और ग्रेफाइट मिलता है। नीमच में लाइमस्टोन, बैतूल में कोल, ग्रेफाइट ग्रेनाइट, लेड और जिंक मिलता है। छिंदवाड़ा में कोल, मैंगनीज और डोलोमाइट मिलता है बालाघाट में कॉपर, मैंगनीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मंडला और डिंडोरी में डायमंड, डोलोमाइट और बॉक्साइट, सिंगरौली में कोल, गोल्ड, आयरन और शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में कोल, कॉल बेड मीथेन, बॉक्साइट, सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट डायस्पोर, आयरन और ग्रेनाइट मिलता है। जबलपुर में डोलोमाइट, आयरन अयस्क, लाइमस्टोन, मैंगनीज, गोल्ड और मार्बल मिलता है। देश में कोयल का उत्पादन 3 लाख 61 हजार 411 मीट्रिक टन है। मध्यप्रदेश में 30 हजार

916 मेट्रिक टन कोल्ड रिजर्व है, जो देश का 8 प्रतिशत है। इसीप्रकार चूना पत्थर देश में 19028.5 मैट्रिक टन है और मध्यप्रदेश में 1692 मिट्रिक टन है, जो देश का 9% है। लौह अयस्क देश में 6209 और मध्यप्रदेश में 54.1 मीट्रिक टन है, जो देश का एक प्रतिशत है। इसी प्रकार तांबा देश में 163.9 मैट्रिक टन है। मध्यप्रदेश में 120.4 मीट्रिक टन है, जो देश का 73 प्रतिशत है। इसी प्रकार मैंगनीज अयस्क 75.0 मीट्रिक टन है। मध्यप्रदेश में 19.6 मिट्रिक टन है, जो देश का 26% है। बॉक्साइट 640.5 मीट्रिक टन है और मध्यप्रदेश में 18.6 मीट्रिक टन है, जो देश का तीन प्रतिशत है। रॉक फॉस्फेट देश में 30.9 मैट्रिक टन रिजर्व है और मध्यप्रदेश में 9.0 मीट्रिक टन है, जो 29% है।

राष्ट्रीय रैंकिंग में भी आगे

राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसी तरह रॉक फास्फेट में दूसरे, चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है।

नियद नेल्लानार योजना से बदल रही गाँवों की तस्वीर

- सीईओ क्रेडा राजेश सिंह राणा ने की समीक्षा
- दिये त्वरित प्रगति के निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 'नियद नेल्लानार योजना' (आपका अच्छा गांव योजना) योजना शुरू की गई है। इस योजना अंतर्गत अन्य विभागों की तरह क्रेडा के भी बहुत से कार्य सम्मिलित है, जिसमें क्रेडा द्वारा योजना के कार्यक्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संबंधित अनेक कार्य किये जाने हैं। इस योजना अंतर्गत जिला सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में आयोजित 21 कैम्पों में सम्मिलित 93 ग्रामों में विभागीय योजनाओं के आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस कार्ययोजना में इन सभी जिलों के 93 ग्रामों में क्रेडा द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं के अंतर्गत सौर सुजला योजना से 380 नग सौर सिंचाई पंप, जल जीवन मिशन से 136 नग सौर पेयजल पंप, चौक चौराहों में 93 नग सोलर हाई मास्ट संयंत्र एवं अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए 03 नग सोलर पावर प्लांट एवं 1219 नग सोलर होम लाईट संयंत्र की स्थापना सम्मिलित है। क्रेडा द्वारा ग्राम सिलगेर में 15 नग होमलाईट, प्रत्येक परिवार को 05 नग एलईडी लाईट, एक नग पंखा एवं मोबाईल चार्जिंग एवं इत्तापारा आंगनबाड़ी-02 तथा पटेलपारा आंगनबाड़ी-01 में सौर संयंत्र क्षमता 600 वॉट सहित टी.वी. की स्थापना कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनांतर्गत अब तक ग्राम टेकलगुड़ा में 17 नग होमलाईट, 600 वॉट क्षमता के 2 नग सौर

संयंत्र सहित टी.वी. की स्थापना एवं प्रत्येक परिवार को 5 नग एलईडी लाईट, एक नग पंखा एवं मोबाईल चार्जिंग प्रदान किया गया है। इस संबंध में क्रेडा द्वारा किये जा रहे कार्यों की स्थिति जानने तथा उन कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए सीईओ क्रेडा राजेश सिंह राणा द्वारा 5 अगस्त को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यक्रम-शाखाओं के अधिकारी, योजनांतर्गत कार्यरत स्थापनाकर्ता इकाई उपस्थित हुए साथ ही क्रेडा के संबंधित जोनल, एवं जिला कार्यालयों के अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।

सर्वप्रथम सी.ई.ओ, क्रेडा द्वारा नियद नेल्लानार योजना (आपका अच्छा गांव योजना) अंतर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु स्थापित किये जा रहे सोलर पंपों की प्रगति के संबंध में संबंधित जिलों के जिला प्रभारियों तथा उन क्षेत्रों में कार्य कर रही इकाईयों से जानकारी ली गई। इकाईयों द्वारा सभी कार्य त्वरित गति से किये जाने के संबंध में जानकारी दी गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में बारिश के कारण अधिकांश परियोजना क्षेत्रों के मार्गों से कट जाने के कारण सामग्री नहीं पहुंचाई जा पा रही है।

क्रेडा, सी.ई.ओ. द्वारा नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत क्रेडा द्वारा सभी परियोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में त्वरित गति से प्रगति लाते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिये गये, साथ ही उनके द्वारा उक्त कार्यक्षेत्रों में कार्य कर रही इकाईयों एवं क्रेडा के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि यह शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है एवं शासन द्वारा इस योजना से संबंधित सभी कार्यों की सतत् समीक्षा की जा रही है। नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत क्रेडा से संबंधित सभी कार्य गुणत्तापूर्वक पूर्ण किये गये योजना से संबंधित किसी भी कार्य में संबंधित इकाई अथवा अधिकारियों द्वारा कोताही बर्ते जाने पर गंभीर रूप से कार्यवाही की जावेगी। जिन इकाईयों को संबंधित कार्यों हेतु एल.ओ.आई. जारी किये जा चुके हैं, उन इकाईयों को त्वरित गति से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर क्रेडा में कार्यादेश हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समयसीमा में ही जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इसी तरह जिन इकाईयों को संबंधित कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, उन इकाईयों को संबधित कार्यस्थलों पर त्वरित गति से कार्यों में गुणवत्तापूर्ण प्रगति लाते हुए समस्त कार्यों को निर्धारित समयसीमा में ही पूर्ण किया जाना होगा। इन प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा न हो अथवा देरी न हो इसलिए यह आवश्यक है कि क्रेडा के संबंधित अधिकारी भी इकाईयों को उन्हें प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आने पर उन समस्याओं के निवारण के लिए पारस्परिक सहयोग प्रदान करे, साथ ही अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों पर निरंतर निगरानी रखते हुए कार्यों को ससमय एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करावें। राज्य के मुख्यमंत्री की मंशानुसार क्रेडा सीईओ राणा द्वारा नियद नेल्लानार योजना में क्रेडा की सहभागिता बढ़ाने एवं तद्नुसार सुविधाविहीन क्षेत्रों में क्रेडा की योजनाओं को प्रदेश के सबसे जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंचाने के संबंध में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं, जिनके अच्छे परिणाम आपका अच्छा गांव (नियद नेल्लानार) योजना के प्रगति के दौरान ही दिखने लगे हैं।

बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ

छत्तीसगढ़ शासन की 'नियद नेल्लानार योजना' (आपका अच्छा गांव योजना) के तहत नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाई जा रही है। उक्त योजनान्तर्गत बुनियादी सुविधायें जैसे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, उचित मुल्य दुकान, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरवेल्स, सोलर पंप, कौशल विकास इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी तारतम्य कौशल विकास विभाग के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित नये कैम्प के चारो ओर आने वाले चयनित ग्रामों में निवासरत् परिवार के युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु सर्वे कर उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुरूप इच्छुक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें अब तक 3107 युवाओं का सर्वे किया गया है, जिसमें से 1554 युवा द्वारा कौशल प्रशिक्षण की इच्छा व्यक्त की गई है, इन इच्छुक युवाओं को क्रमशः जिला बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत 85 युवाओं को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, अस्सिटेंट इलेक्ट्रीशियन, हैंड एम्ब्रॉयडर, टू-व्हीलर सर्विस अस्सिटेंट, सीनियर ऐसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, हॉफपेन्ट मैकिंग, एवं लैडिज गॉरमेंट मैकिंग कोर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हरे सोने से वनाश्रितों की बढ़ी चमक

तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ी तो अधिक मुनाफा

हरा सोना के नाम से ख्यात तेंदूपत्ता का संग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त आय का एक पूरक स्त्रोत है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर तेंदूपत्ता का संग्रहण लघु वनोपज के रूप में किया जाता है। लाखों ग्रामीण इस कार्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है। जिससे संग्राहकों को पहले के 4 हजार प्रति मानक बोरा की तुलना में 15 सौ रुपए अधिक मिल रहे है। इससे संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण से होने वाली आय बढ़ी है। रायगढ़ जिले की बात करें तो 98 हजार 977 संग्राहकों को 68 करोड़ 68 लाख 11 हजार 180 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बढ़ी दरों के लिहाज से जिले के संग्राहकों को 18.73 करोड़ रुपए ज्यादा मुनाफा मिला है।

जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ के प्रबंध संचालक ने बताया कि रायगढ़ जिला अंतर्गत दो जिला वनोपज सहकारी यूनियन रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ में वर्ष 2024 तेन्दूपत्ता सीजन में 112 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 94 लॉट निर्धारित है। जिले में संग्रहण हेतु 747 संग्रहण केन्द्र में संग्रहण कार्य हेतु 1 लाख 40 हजार 600 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें तेन्दूपत्ता संग्रहण लक्ष्य के विरूद्ध 1 लाख 24 हजार 874.760 मानक बोरा संग्रहण किया गया है। इस वर्ष संग्रहण

की दर 5500 रुपये प्रति इस वर्ष संग्रहण की दर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा (550 रुपये प्रति सौ गड्डी)निर्धारित है। गेरवानी समिति फड़ सराईपाली के अमृत लाल अगरिया एवं उनकी पत्नी पुना अगरिया ने बताया कि सीजन में उन्होंने 3640 तेन्दूपत्ता गड्डी तोड़कर उसका विक्रय किया था, जिससे उन्हें 20 हजार 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि पुरानी दर के मुकाबले उन्हें प्रति मानक बोरे की दर बढने से लगभग साढ़े पांच हजार रूपए ज्यादा मिले। प्राप्त धनराशि को वे खेती-किसानी में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संवेदनशील निर्णय से हम संग्राहकों को पहले से ज्यादा राशि मिल रही है, जो हमारे लिए अतिरिक्त आय का आधार बन रहा है। इसी तरह गेरवानी समिति फड़ गौरमुड़ी के श्री नथीराम एवं उनकी पत्नी सुखमनी ने बताया कि उन्होंने 3420 तेन्दूपत्ता गड्डी तोड़कर उसका विक्रय किया था, जिससे उन्हें 18 हजार 810 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। प्राप्त रूपये से उन्होंने बरसात में होनी वाली परेशानी को देखते हुए खप्पर वाला घर के छत की मरम्मत कराकर उसमें एस्बेस्टस की छत डलवाए हैं और डोली खेत में भी राशि खर्च की है।

'जशप्योर' उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री देश भर मे

छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अपनी हरी-भरी वादियों के और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जिला लोगों को प्रकृति से जोड़ता है और ताजगी का अनुभव करता है। जैसे-जैसे मानसून आता है इसकी खूबसूरती और निखरकर सामने आती है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का मेल अद्वितीय है। इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है 'जशपुर ब्रांड' जो आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करता है। अब यह ब्रांड केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी जगह बना चुका है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।

महिला समूह की मेहनत का प्रतिफल है जशप्योर

जशपुर जिला हर क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। यहां की महिलाएं भी कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। "जशपुर ब्रांड" इसी का एक बेहतर उदाहरण और उत्कृष्टता का प्रतीक है। "जशपुर ब्रांड" के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद ढेकी कुटा जवा फूल चावल, जो कि अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए इस चावल की सुगंध और स्वाद अनूठा है। वही महुआ और मिलेट लड्डू जो महुआ और मिलेट से बने यह लड्डू पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। यह लड्डू विशेष रूप से बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं।

जशप्योर के उत्पादों की देश भर में डिमांड

इसी तरह मिलेट आधारित पास्ता, यह पास्ता पारंपरिक गेहूं के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है, जो स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के लिए एक उत्तम विकल्प है। इनके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाऊ एवं महुआ से बने विभिन्न उत्पाद संपूर्ण भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं। जशपुर ब्रांड के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक, "जशपुर ब्रांड" के उत्पादों को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक गुण।

जशप्योर से जुड़ी महिलाएं बनी आत्मनिर्भर

जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सफल प्रयास है। इस ब्रांड के माध्यम से इन महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। जशप्योर द्वारा निर्मित 'जशपुर ब्रांड' का हर उत्पाद इन महिलाओं की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। जशपुर ब्रांड के उत्पाद अब रीचनतमण्बवउ पर उपलब्ध हैं, जहां से इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही, देशभर में विभिन्न ऑफलाइन स्टोर्स पर भी ये उत्पाद उपलब्ध हैं, जो इस ब्रांड की व्यापक पहुंच का प्रमाण हैं।

जशप्योर को लोकप्रिय बनाने प्रशासन प्रयासरत

जशप्योर का यह जशपुर ब्रांड केवल एक व्यापारिक नाम नहीं है, बल्कि यह आदिवासी महिलाओं के परिश्रम, समर्पण और गुणवत्ता की एक कहानी है। जशपुर ब्रांड के माध्यम से अब पूरे भारत में लोग इस स्वाद और गुणवत्ता का आनंद उठा रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। यह ब्रांड भविष्य में और अधिक लोकप्रिय हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसका अब सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

आखिरकार क्यों देश छोड़ गई शेख हसीना?

◦ शेख हसीना ने इस्तीफे की घोषणा की

बांग्लादेश में जारी आरक्षण आंदोलन में जारी हिंसा फिलहाल थमती नहीं दिख रही। इसमें शेख हसीना की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और चुपचाप देश से निकल गईं। पहले उनके ब्रिटेन जाने की चर्चाएं थीं लेकिन वहां के आव्रजन नियमों के चलते फिलहाल उनकी ये योजना खटाई में पड़ गई है। गौरतलब है कि जब तक शेख हसीना ने देश नहीं छोड़ दिया था तब तक कोई इस बात को सोंच भी नहीं सकता था कि तीन दशक तक मजबूती से देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली पीएम देश से पलायन भी कर सकती हैं।

बांग्लादेश में कई नाटकीय घटनाक्रम देखे गए। इसमें जेल में बंद कई नेताओं के जेल से रिहा करने, देश में भीषण हिंसा शामिल हैं। दरअसल देश में हालात बेकाबू हो गए थे। जारी हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी। इस बारे में शेख हसीना को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन वे अपने रुख से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें लगा की सेना की मदद से आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग कर वे स्थिति को काबू में ले आएंगी, लेकिन उनका अनुमान उलटा साबित हुआ। सेना ने भी उनका साथ छोड़ दिया और स्थिति और जटिल हो गई। इसके बाद ही पूर्व पीएम हसीना ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। इस बारे में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने भी बताया था। उन्होंने कहा कि उनकी मां रविवार को ही इस्तीफा देने का विचार बना रही थीं।

क्या थी आखिरी वक्त पर हसीना की योजना?

हालांकि आखिरी वक्त तक शेख हसीना की योजना के बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सेना के एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि पूर्व पीएम ने कब अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए और कब वे देश से निकल गईं इस बारे में सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, प्रेसिडेंट गार्ड और सेना के शीर्ष अधिकारियों को ही मालूम था। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को बेहद गोपनीय रखा गया था।

दोनों विकल्प चाहती थीं हसीना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आखिरी वक्त तक शेख हसीना सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थीं। वे अपने लिए दोनों विकल्प खुले रखना चाहती थीं। पहला यह कि वे देश छोड़कर बाहर चली जाएं और दूसरा यह कि बल प्रयोग के जरिए अपने आखिर तक सत्ता में बनी रहें। हालांकि सेना को हिंसा और उसमें मरने वालों की संख्या में और बढोतरी मंजूर नहीं थी।

हसीना के देश छोड़ने में सेना ने भी की मदद

वहीं, कई रिपोर्ट्स में बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों से वार्ता के आधार पर दावा किया गया है कि हसीना को देश से निकालने में सेना ने भी सहयोग किया था। इस बाबत तय योजना के मुताबिक ही गणभवन जाने वाले कई रास्तों पर सुबह से ही पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा जमा रखा था। ताकि वे सुरक्षित रूप से तेजगांव एयरपोर्ट तक पहुंच सकें। वहीं, सोमवार को ही उनके देश से निकलने से पहले देश में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था ताकि उनको लेकर कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर न फैल सके।

देश छोड़ने से पहले सेना और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

यह भी सामने आया है कि शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले सोमवार को सेना और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्हें बताया गया था कि स्थिति अब बेकाबू हो गई है। आंदोलनकारी गणभवन का रुख कर सकते हैं, और उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर वे गणभवन (शेख हसीना का निवास) तक पहुंच गए तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में उनके लिए देश छोड़ना ही बेहतर विकल्प था। वहीं, अधिकारियों ने यह भी बताया कि देश के बाहर निकलने के बाद उनके अगले ठिकाने को लेकर भारत से पहले ही बात हो चुकी थी। जिसमें भारत ने कहा था कि अगर वे अगरतला तक आ जाती हैं तो उन्हें दिल्ली लाया जाएगा।

बांग्लादेशी नागरिकों ने दी प्रतिक्रिया

भारत पहुंचने के बाद एक नागरिक ने बांग्लादेश की स्थिति पर मीडिया से बाद की। उन्होंने कहा, 'स्थिति नियंत्रण में हैं, मैं भारत केवल इलाज के लिए आया हूं।'एक दूसरे नागरिक ने भी मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ष्अब सब कुछ वहां ठीक है। वहां कोई समस्या नहीं है। खूब नरसंहार हुए और कई छात्र मारे गए। मैं यहां घूमने आया हूं।

क्या था हिंसा का कारण

बता दें कि सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। जिसके बाद इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक हो चुकी है।

नए कीर्तिमान खड़ा कर दी मनु भाकर

◦ पिता ने कहा- मुझे बेटी पर गर्व है ◦ 12 साल बाद किसी निशानेबाज ने जीता मेडल

पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर स्वदेश लौट आई. इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकलीं, उनके माता-पिता ने उन्हें गले लगाकर उनका माथा चूम लिया. मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी सभी ने जोरदार स्वागत किया. मनु भाकर के एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उनके माता-पिता, परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के लोग भी पहुंचे. मनु भाकर के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले टर्मिनल-3 भारत माता के जयकारों से गूंज उठा. मनु भाकर के कोच जसपाल राणा मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मनु भाकर की जीत में उनका बड़ा योगदान है. इसलिए न सिर्फ मनु भाकर के लिए बल्कि उनके कोच जसपाल राणा के लिए भी समर्थकों में उत्साह दिखा.

पिता ने कहा- मुझे बेटी पर गर्व है

इस मौके पर कोच जसपाल राणा के पिता नारायण राणा भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि एक ओलंपिक में दो पदक जीतकर मनु ने इतिहास रचा है. हमें बहुत खुशी है. निशानेबाजी के लिए यह ऐतिहासिक पल है और भविष्य में इससे भी ज्यादा पदक की उम्मीद होगी. सबका ध्यान इस खेल की ओर आया है और भविष्य में खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे. एयरपोर्ट पर मौजूद मनु भाकर के पिता ने कहा, ष्मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मनु ने ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया.

12 साल बाद किसी निशानेबाज ने जीता मेडल

भारत की मनु भाकर ने पेरिस में दोहरी जीत से पहले निशानेबाजी दल का 12 साल का सूखा समाप्त किया. युवा भारतीय निशानेबाज मनु भाकर बुधवार सुबह भारत पहुंचीं. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसक ओलंपिक पदक विजेता का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े. न सिर्फ उन्होंने शूटिंग में भारत का सूखा खत्म किया, बल्कि पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया और 10 मीटर मिश्रित टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर एक और कांस्य पदक जीतकर इसे दोगुना कर दिया.

क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फिर पेरिस जाएंगी मनु

25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्हें चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा, जिससे उनका ओलंपिक अभियान रिकॉर्ड दो पदकों के साथ समाप्त हुआ. मनु पेरिस ओलिंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी. मनु रविवार को होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस जाएंगी.

युवा अवस्था में ही भारत की बन गई शूटिंग स्टार

युवा अवस्था में ही मनु भाकर रैंकिंग के माध्यम से भारत की शूटिंग स्टार बन गई। भारत का हरियाणा राज्य मुक्केबाजों और पहलवानों के नाम से जाना जाता है, यहां कि मिट्टी से निकले एथलीटों ने पूरी दूनिया में अपना परचम फहराया है।

हमारी इस कहानी में हम बात करेंगे शूटिंग गर्ल मनु भाकर की, हरियाणा के झज्जर में जन्मीं मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली थ्थान टाश नामक एक मार्शल आर्ट में भी भाग लिया। 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म ही हुआ था। इसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपने पिता से शूटिंग पिस्टल लाने को कहा। उनके हमेशा साथ देने वाले पिता राम किशन भाकर ने उन्हें एक बंदूक खरीदकर दी और वो एक ऐसा फैसला था जिसने एक दिन मनु भाकर को ओलंपियन बना दिया। 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चौंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपियन और पूर्व विश्व नंबर-1 हीना सिद्धू को चौंकाते हुए 242.3 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी बदौलत उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में हीना को हरा दिया.

“कौन जात हो”

जाति जनगणना की मांग करने वाले राहुल गाँधी ने चुनावों के दौरान ‘जितनी आबादी-उतना हक’ का नारा बुलंद किया। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इतिहास में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने कभी भी जाति और आरक्षण का समर्थन नहीं किया। पंडित नेहरू, उनकी सुपुत्री इंदिरा गाँधी और इनके पुत्र राजीव गाँधी ने जातिवाद की राजनीति और आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। जब वर्षों से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ खड़ा है, तब जाति जनगणना की नई मांग मुस्लिम कोटा के लिए रास्ता बनाने की दिशा में शायद एक नया कदम है?

दशकों से ये सवाल भारत की एक बड़ी आबादी से पूछा जाता रहा है। ‘भेदभाव’ ही इस प्रश्न का एकमात्र उद्देश्य और परिणाम है। अगड़ी जाति के लोगों ने इसका उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों की पहचान करने, उन्हें ‘उनकी’ तरह का काम प्रदान और उनके साथ अलग व्यवहार करने के लिए किया है। हालाँकि जाति व्यवस्था हमेशा कर्म आधारित रही है, लेकिन हम किसी तरह इसे जन्म के आधार पर वर्गीकृत करने में कामयाब रहे हैं, और हाल की घटनाएं इस युग की वापसी की ओर इशारा कर रही हैं। हाल ही में लोकसभा में बहस के दौरान अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर हंगामा मच गया। अखिलेश यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है?

इन सभी घटनाओं के बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा पत्रकार का नाम और उसके मालिक का नाम पूछने और अखिलेश यादव द्वारा पत्रकार की जाति पूछने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जाति जनगणना की मांग करने वाले राहुल गाँधी ने चुनावों के दौरान ‘जितनी आबादी-उतना हक्र’ का नारा बुलंद किया है। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन जी ने यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इतिहास में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने कभी भी जाति और आरक्षण का समर्थन नहीं किया। पंडित नेहरू, उनकी सुपुत्री इंदिरा गाँधी और इनके पुत्र राजीव गाँधी ने जातिवाद की राजनीति और आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी का बदला हुआ चाल चरित्र और चेहरा एक चिंतनीय विषय है। हाल में अमेरिका में कमला हैरिस ने भी कहा कि अगर ट्रम्प चुनकर आए तो वो देश का संविधान बदल देंगे। अब अगर इन बयानों को जोड़ें तो एक श्रृंखला नजर आती है। जब वर्षों से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ खड़ा है, तब जाति जनगणना की नई मांग अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मुस्लिम कोटा के लिए रास्ता बनाने की दिशा में शायद एक नया कदम है?

27 जून 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र में जाति-आधारित आरक्षण पर अपने

- उज्ज्वल वीरेंद्र दीपक
कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यू यॉर्क से MPA

विचार व्यक्त किये। उन्होंने घोषणा की कि ‘मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है। खासकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अक्षमता को बढ़ावा देता है और हमें सामान्यता की ओर ले जाता है।’ नेहरू ने भारत में सामाजिक न्याय के सबसे महान उपायों में से एक, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा सपना था, को ‘अक्षमता’ और ‘औसत दर्ज’ को बढ़ावा देने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।

नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी ने 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार द्वारा आदेशित मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वास्तव में, उन्होंने जाति आधारित पार्टियों का मुकाबला करने के लिए एक नारा गढ़ा था ‘ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर’। इंदिरा गाँधी के पुत्र, राजीव गांधी ने भी मंडल रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था। जब पीएम रहते हुए वी.पी. सिंह ने ओबीसी आरक्षण लागू किया तो राजीव ने इसे देश को जातिगत

आधार पर बांटने की कोशिश बताया। वास्तव में, 3 मार्च, 1985 को एक अखबार को दिए एक साक्षात्कार में, राजीव गांधी ने बयान दिया कि आरक्षण के नाम पर 'बुद्धओं' को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। सितंबर 1990 में विपक्ष के नेता के तौर पर राजीव ने वीपी सिंह की तुलना उन अंग्रेजों से की थी जिन्होंने देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटा था।

राजीव गाँधी के पुत्र राहुल गांधी ने 2022 में जाति जनगणना का आह्वान किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में जाति जनगणना की और रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक किए बिना उसे ठन्डे बस्ते में डाल दिया। राहुल आसानी से भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान द्वारा अनिवार्य एससी/एसटी आरक्षण को मुसलमानों के पक्ष में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (1981) और जामिया मिलिया इस्लामिया (2011) से हटा दिया गया, भले ही दोनों सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। यह नेहरू-गांधी राजवंश द्वारा दिखाए गए पाखंड के कई कृत्यों में से एक है। 2011 में, यह राजद जैसे कांग्रेस के सहयोगी ही थे जिन्होंने जाति जनगणना कराने के लिए यूपीए पर दबाव डाला, जिससे कांग्रेस की दशकों से ऐसा न करने की घोषित नीति की स्थिति पलट गई। 2011 में भी, पी चिदंबरम, आनंद शर्मा और पवन कुमार बंसल जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना पर आपत्ति जताई थी और मंत्रियों का एक समूह इस पर कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया।

4,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले सर्वेक्षण को पूरा करने में पांच साल लग गए लेकिन इसमें तकनीकी खामियां थीं और यह कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना के खिलाफ राजवंश के रुख का भी हवाला दिया।

राहुल गांधी ने लोकसभा के लिए अपने चुनाव अभियान को एक स्वर में इस आह्वान पर केंद्रित किया कि भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी और भारत के संविधान को बदल देगी। जनता ने इंडी गठबंधन से ज्यादा सीटें भाजपा को दीं। राहुल ने सबक नहीं सीखा। दरअसल, जाति जनगणना और अंतर्निहित जातिवाद के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम कोटा बनाने की नीति में महारत हासिल कर ली है। अतीत में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए दो मॉडल अपनाए थे। पहला कर्नाटक में था जहां पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली ने 1994 में ओबीसी के भीतर ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले मुसलमानों, बौद्धों और अनुसूचित जातियों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। दूसरा मॉडल आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, जहां पूर्व कांग्रेस सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की। कांग्रेस के 2009 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी रोजगार और शिक्षा में आरक्षण का बीड़ा उठाया है। हम इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' यूपीए सरकार के तहत 2004 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति एक उदाहरण है। रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग ने एससी/एसटी आरक्षण को समाप्त करने की योजना बनाई थी। चाहे वह अनुसूचित जातियों का डी-शेड्यूलिंग हो, या एससी/एसटी आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा तय करने की सिफारिश हो। यह चिंताजनक है कि छह दशक से अधिक के कांग्रेस शासन को राहुल गांधी भूल गए हैं। यह प्रासंगिक नहीं लगता कि राहुल के सलाहकारों ने उनसे पार्टी की नीति को त्यागने के लिए कहा हो। अधिक संभावना यह प्रतीत होती है कि राहुल से कहा गया है कि वे केवल मुस्लिम आरक्षण के लिए रास्ता बनाने और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जाति जनगणना पर जोर दें।

धन के पुनर्वितरण के साथ जुड़े विचार, और कांग्रेस की सोच कि 'अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है' इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण का लाभ छीनकर अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों को देने के लिए प्रतिबद्ध है।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के पिछले दशक ने निश्चित रूप से विभाजनकारी कांग्रेस नीतियों के पुनरुद्धार में मदद नहीं की है और इसलिए जाति जनगणना भारत को और अधिक विभाजित करने की एकमात्र उम्मीद लगती है।

(ये लेखक के अपने निजी विचार हैं)

ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हर लुक में बेहद हॉट सनी लियोनी

सनी का हर स्टाइल फेमस

सनी लियोनी की हर तस्वीर काफी खूबसूरत होती हैं। उनका ड्रेसिंग स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता है। वे अक्सर अपना टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। सनी अपने इंस्टाग्राम पर कभी ट्रेडिशनल तो कभी ग्लैमरस लुक शेयर करती हैं। सनी के वन पीस लुक फैशन इंस्पायरिंग होते हैं। ये सभी लुक में वे काफी खूबसूरत दिखाई देती हैं। बता दें कि सनी ने साल 2012 में पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद उनके पास फिल्म जैकपॉट और रागिनी एमएमएस 2 आई। ये सभी फिल्म सुपरहिट साबित हुई।

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक सनी लियोनी ने इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, उन्होंने बोल्ड और इंटिमेट सीन्स देकर अपना एक अलग ही लेवल सेट कर लिया है, उन्हें सबसे ज्यादा फेम अपने इन्हीं सीन्स के कारण मिली है। सोशल मीडिया पर वे काफी एक्टिव रहती हैं। अपनी तरह-तरह की फोटोज के साथ वे फैंस को अपडेट देती रहती हैं। फिलहाल सनी एमटीवी के रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 15 को होस्ट कर रही हैं।

अधिकतर आयटम सॉन्ग्स किए

सनी ने इसके बाद फिल्म एक पहेली लीला में काम किया। यह फिल्म इतनी हिट नहीं हो पाई, लेकिन सनी ने अपनी बोल्डनेस से कमाल जरूर कर दिया। सनी को अधिकतर बॉलीवुड फिल्मों में आइटम सॉन्ग करते देखा गया है। बता दें कि सनी के पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता हैं। इतना ही नहीं, सनी बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। सनी लियोनी के वर्कफ्रंट करें, तो वे जल्द ही फिल्म कोटेशन गैंग में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनका एक्शन अंदाज देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा सनी लियोनी 'कैनेडी' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। यह अनुराग कश्यप के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन है। उनके पास एक अनटाइटल्ड मलयालम फिल्म भी है।

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Approved by : PCI | AICTE | NCTE | BCI | Member of : AIU | Recognized by : UGC | A NAAC Accredited University

(Accredited "A Grade" by NAAC)

NO AMOUNT OF MONEY CAN GIVE THE HAPPINESS THAT FREEDOM DOES.

LONG LIVE OUR NATION.

15th AUGUST

HAPPY INDEPENDENCE DAY

CONTACT FOR MORE DETAILS:

ADMISSION HELPLINE
6261-900581/82

Scan to visit

Kargi Road, Kota, Dist.- Bilaspur (C.G.)
Ph. +91-7753-253801,
Email: info@cvru.ac.in, admissions@cvru.ac.in
Website: www.cvru.ac.in

AdPRAYAS

City Office: Dr. C.V. Raman University, Infront of Pallav Bhavan, Ring Road No.2, Bilaspur (C.G.) Ph. 07752-448799, Mo. 9109028878

RO. No.:- 12891/ 217